महेंद्र सिंह एडवोकेट को डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन करनाल का प्रधान चुना गया

करनाल। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा वर्ष 2021 -22 के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया था जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन करनाल के पदाधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई व चुनाव की प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग ऑफिसर श्री प्रेम सागर बटला व सहायक रिटर्निंग अफसर श्री राहुल गुप्ता की देखरेख में पदाधिकारियों का चुनाव हुआ प्रत्येक पद के लिए एक-एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया श्री महेंद्र सिंह एडवोकेट ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया व श्री पंकज दुआ ने उप प्रधान पद के लिए व श्री शिव गुप्ता ने सेक्रेटरी के पद के लिए वह श्री संदीप जैन ने सह सचिव के पद के लिए तथा श्री नवनीत सिंह ने खजांची के पद के लिए नामांकन दाखिल किया सभी सदस्यों ने उपरोक्त पदाधिकारियों पर सहमति जताई अत: उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से चुना गया इस अवसर पर रिटर्निंग अफसर श्री प्रेम सागर बटला जी ने आज बैठक बुलाई जिसमें की मुख्य अतिथि वरिष्ठ सदस्य बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एडवोकेट श्री भूपेंद्र सिंह राठौर को आमंत्रित किया गया व भूपिंदर सिंह राठौर जी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई इस अवसर पर श्री मनोज मित्तल एडवोकेट श्री सुरेंद्र रोहिल्ला एडवोकेट श्री सुरेश शर्मा श्री नरेश गुप्ता श्री संजय मदान श्री संजय पुरी श्री कमल ढींगरा श्री कीर्ति गोयल श्री भीम सिंह श्री रमन मल्होत्रा श्री दीपक रोहिल्ला व अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

सरकार लगातार चला रही नशा विरोधी मुहिम : मनोहर मुख्यमंत्री का दावा

करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें लगातार नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, इसके लिए सरकार निरंतर नशा विरोधी मुहिम चला रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने करनाल दौरे के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत नई अनाज मंडी में आयोजित संकल्प समारोह में विद्यार्थियों को संकल्प दिलवा रहे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पहले नशा मुक्ति मुहिम के तहत शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे की लत बेहद बुरी है। जो नशा करने लगता है, उसे सूझ-बूझ नहीं रहती। उसे संभालना पड़ता है। विभिन्न तरह का नशा करने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का क्षय होता है और वह कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने की बजाए नशे में लिप्त आदमी कमाई को नशे में खर्च करने लगता है। परिवार से दूर हो जाता है। समाज की बदनामी होती है। आज हमें इस नशे की लत को दूर करने की जरुरत है। इसके खिलाफ समाज के हर वर्ग को नशा मुक्ति अभियान चलाया जाना चाहिए। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर के युवा बेटे का उदाहरण देते हुए कहा कि नशे की लत में कौशल किशोर ने अपना बेटा खो दिया। पूरे परिवार के सदस्यों के लिए पीड़ा की बात थी। आज वे देशभर में घूम-घूमकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके इस प्रयास की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे की विरोधी है। आज समाज में दो वर्ग हैं, एक वर्ग नशा करने वाला है और दूसरा नशे का विरोध करने वाला है। हमें निरंतर नशा मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि हम न नशा करेंगे, न इसको बढ़ावा देंगे और जो नशा करते हैं, उनकी आदत को भी सुधारेंगे।

करनाल वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

ईश गुलाटी, पार्षद

नगर निगम करनाल वार्ड 13

शुगर मिल की टरबाइन फ़ेल, उत्पादन ठप, किसानों का गन्ना बर्बाद

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

करीब 284 करोड़ खर्च करके हरियाणा सरकार ने करनाल की सहकारी चीनी मिल का नवीकरण इस लिये कराया था ताकि गन्ने की पिड़ाई क्षमता 20-22 हजार क्विंटल प्रति दिन से बढा कर 35000 क्विंटल तक की जा सके। जाहिर है यह खर्च, सरकार की आय बढाने को तो किया ही गया है, साथ ही किसानों के अधिक गन्ने पिड़ाई होने से उनकी आय बढ़ना भी निश्चित समझा गया था। परन्तु इतना भारी खर्चा करने के बावजूद मिल की स्थिति पहले से भी बद्तर हो गयी। इसके परिणामस्वरूप किसानों के गन्ने की भी दुर्गति हो रही है।

इसी वर्ष के अप्रैल में नवीकृत मिल को 45 दिन के ट्रायल पर चलाया गया था। उस वक्त पुरानी मशीनें भी चल रही थी, जाहिर है पुरानी मशीनों के बूते ट्रायल को कामयाब घोषित कर दिया गया। मिल में नई लगी बिजली पैदा करने वाली जिस टर्बाइन को फ़िट घोषित कर दिया गया था वह आठ दिसम्बर को यकायक फेल हो गयी जिसकी वजह से चलती मिल खड़ी हो गयी। इस तरह से यकायक मिल के थम जाने से लाखों रुपये का वह अधबना माल बिगड़ कर किसी काम का नहीं रहता।

जैसे-तैसे करके टर्बाइन ठीक कराने के लिये मिल के डिप्टी चीफ़ इन्जीनियर व ठेकेदार के एक आदमी को हवाई जहाज़ के द्वारा बैंगलोर भेजा गया। वहां से कुछ सामान लाकर टर्बाइन 11 दिसम्बर को फ़िर से चलाई गई तो मात्र डेढ दिन चलने के बाद फ़िर से फ़ेल हो गयी। परिणाम फ़िर वही लाखों रुपये का अधबना माल बर्बाद। फ़िर मरम्मत करके 13 तारीख

को टर्बाइन फ़िर से चालू की गयी।

मिल की इस बिगड़ी स्थिति के चलते गन्ने की औसत पिड़ाई बमुश्किल 25-26 हजार क्विंटल प्रतिदिन ही हो पा रही है। जाहिर है इससे मिल के साथ-साथ किसानों को भी भारी घाटा लग रहा है। यहां गौरतलब यह भी है कि मिल के नवीकरण का यह भारी भरकम ठेका नोयडा की जिस आइजेक कम्पनी को दिया गया है उसका असल मालिक डीडी पुरी है जो यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल का मालिक है। समझने वाली बात तो यह है कि उसकी अपनी मिल तो कभी खराब होती नहीं सुनी गयी, उसमें तो धका-धक, क्षमता से भी अधिक उत्पादन हो रहा है और मोटा मुनाफ़ा कमा रहा है, फ़िर उसी द्वारा नवीकृत करनाल की इस मिल को क्या मौत पड़ रही है?

दरअसल, करनाल समेत लगभग सभी सरकारी मिलों पर हरामखोरी व रिश्वतखोरी की मार पड़ रही है।

प्राइवेट मिलों द्वारा किये जाने वाले शोषण से किसानों को बचाने के लिये, किसानों के सहयोग से सरकार ने सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की थी। भयंकर रिश्वतखोरी के चलते अधिकांश मिलें तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, शेष बची-खुची दो-चार मिलें भी, भ्रष्टाचार के चलते शीघ्र बंद होने के कगार पर हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये तमाम मिलें सदैव घाटे में ही रहती हैं। करनाल शुगर मिल किसी जमाने में भारी मुनाफ़ा कमाती रही है। यहां के एक एमडी विमल चन्द्र इस लाइन के इतने विशेषज्ञ एवं दक्ष माने जाते थे कि इन्द्री के निकट भादसों स्थित पिकेडली शुगर मिल मालिक ने अपनी डूबती हुई मिल को उबारने के लिये सरकार से कह कर उन्हें अपने यहां प्रतिनियुक्ति पर रखा था।

इस सहकारी मिल का प्रबन्धन करने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो एचसीएस अधिकारी होता है, उसके ऊपर जिले का उपायुक्त बतौर चेयरमैन रहता है। इसके अलावा चण्डीगढ़ में बैठे एक कमिश्नर जो राज्य भर की चीनी मिलों का प्रबंधन देखते हैं। सहकारी मिल होने के नाते इसमें इलाके के किसानों की भी भागीदारी होती है। किसानों की और से आठ निदेशक भी प्रबंधक मण्डल में होतें हैं इनके अलावा इलो का विधायक भी इस प्रबंधन में रहता है। किसानों के चुने हुए आठ डायरेक्टर की कोई सुनवाई नहीं होती। केवल सरकारी अधिकारी ही सारा खेल खेलते हैं।

मीडिया पर आरोप लगाने से पहले राहुल अपने गिरेबान में झांकें : डॉ. चौहान

करनाल । संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। इस पार्टी को अपनी निजी कंपनी के तौर पर चलाने वाला गांधी परिवार लोकतंत्र के स्तंभों पर कीचड़ उछालना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। असहज सवालों से बचने के लिए राहुल गांधी द्वारा एक पत्रकार को सरकार का दलाल बताया जाना यही साबित करता है। यह टिप्पणी हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने राहुल के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए की जिसमें उन्होंने लिंचिंग संबंधी पूछे गए एक सवाल पर पत्रकार को सरकार का दलाल कहा था।

डॉ. चौहान ने कहा कि आजादी के बाद 50 सालों तक लगातार सत्ता सुख भोगने के कारण गांधी परिवार अब खुद को बोर्न टू रूल समझने लगा है। अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दरबारी पत्रकारों की एक ऐसी फौज तैयार की थी जो गांधी परिवार से असहज करने वाला कोई भी कठिन सवाल नहीं पूछता था। बदले में ऐसे पत्रकारों को तरह-तरह

के उपहारों से नवाजा जाता था।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के इन दरबारी पत्रकारों की जमात आज लुटियंस मीडिया के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के शासनकाल में लुटियंस पत्रकार शीर्ष पार्टी नेता सोनिया गांधी से नूडल और पास्ता से ज्यादा कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाए, यह सबने देखा है। आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार के आगे मीडिया को लेट जाते हुए भी सबने देखा है। अब अभिव्यक्ति की आजादी मिलने पर पत्रकार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने लगे हैं तो राहुल गांधी को सहन करना मुश्किल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि वर्ष 2014 से पहले उन्होंने लिंचिंग शब्द सुना तक नहीं था। इस पर पत्रकार ने उनसे कांग्रेस शासनकाल में हुई लिंचिंग से संबंधित कड़े सवाल पूछे थे।

डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुआ सिखों का नरसंहार लिंचिंग की क्रूरतम और वीभत्स घटनाओं में से एक है। देश विभाजन के बाद जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कबूतर उड़ाकर तिरंगा फहराने में व्यस्त थे, उस समय भी देश भयानक लिंचिंग के दौर से गुजर रहा था। गांधी और नेहरू के रहते देश में करीब 20 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। 90 के दशक में हुआ कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार लिंचिंग का भयानक मंजर याद दिलाता है। डॉ. चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए।